भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2533

<u>दिनांक 16 दिसम्बर,2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

मोबाइल निर्यात में वृद्धि

2533. **श्री संजय दिना पाटील:**
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सामान्य मौसमी मंदी को दरकिनार करते हुए सितंबर में मोबाइल निर्यात में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं और निर्यात वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्र या कंपनियाँ कौनसी हैं;

(ग) मुंबई, पुणे और नासिक सहित महाराष्ट्र स्थित मोबाइल विनिर्माण और असेंबली इकाइयों का समग्र मोबाइल निर्यात में कितना योगदान हैं;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र से मोबाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु पीएलआई योजना के तहत कोई प्रोत्साहन प्रदान किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) महाराष्ट्र में मोबाइल विनिर्माताओं के लिए उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच को और बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र से मोबाइल निर्यात को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत सहयोग या बुनियादी ढाँचा विकास शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सितंबर 2025 में, स्मार्टफोन का निर्यात (एचएस कोड 85171300) 1681.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सितंबर 2024 के 922.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 82% की वृद्धि को दर्शाता है।

(ख): स्मार्टफोन के निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार की उन नीतियों के कारण है जिनका उद्देश्य भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। एप्पल और सैमसंग दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका निर्यात बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान है।

(ग): अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान स्मार्टफोन का निर्यात 13.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें महाराष्ट्र का योगदान 309.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

(घ) से (च): भारत सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित "मेक इन इंडिया"विनिर्माण के मिशन के तहत सरकार का निरंतर फोकस और निर्यात संवर्धन मिशन अखिल भारतीय स्तर की पहलें हैं, जो किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं हैं। इसके अलावा, इन योजनाओं का लाभ उन कंपनियों को दिया जाता है (जिन्हें उचित प्रक्रिया के बाद चुना जाता है), जो अपनी इकाइयों का स्थान तय करती हैं। स्मार्टफोन विनिर्माण सहित बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 10 कंपनियों को मंजूरी प्रदान की गई है , जिनमें से कोई भी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है।

*****